

## ओडिशा की 5T पहल

### प्रलिस के लयल:

ओडलशल की 5T पहल, टीड वरक, [राज्य सतर पर नीतलआयोग जैसा ढडल](#), [पारदरशतल](#), प्ररदयोगकी, समय और परवलरतन, सारवजनकी सेवाओं का प्रभावी वतलरण

### ढेनस के लयल:

ओडलशल की 5T पहल, राज्य सतर पर नीतलआयोग जैसा ढडल, वढलनन कषेत्रों ढें वकलस के लयल सरकारी नीतललल और हसतकषेप तथल उनके डलललन एवं कारयानवयन से संबधतल ढुदुदे

[सरोत: हदुलस्तान टाइडस](#)

## चरुा ढें कयों?

ओडलशल का 5T पहल एक शासन वयवस्था ढडल है जो **टीड वरक**, **पारदरशतल**, **प्ररदयोगकी**, **समय-सीडल** और **बदललव** के लयल प्रयुक्त है, जसल शासन वयवस्था ढें सुधार तथल सारवजनकी सेवाओं के कुशल वतलरण सुनशलुतल करने के उदुदेश्य से शुरु कयल गयल है ।

- 5T एजेंडल के अनुरुप ओडलशल सरकार ने अक्तूबर 2019 ढें 'ढो सरकार' यल 'ढलई गवरनढेंट' पहल शुरु की, जसल [राज्य सतर पर नीतलआयोग जैसे ढडल के रूप](#) ढें ढी देखा जलतल है ।
- वर्ष 2022 ढें ओडलशल सरकार के प्रढुख ने 5T पहल ढें एक और T (यलतुरल) को शलढलल करते हुए 6T का ढंतर दयल, ढंतरलल से और अधकी 'ढरढण' करने तथल जढीनी सतर पर सुदुदुढीकरण की दशल ढें कारय करने का आहवलन कयल ।

## 5T पहल:

- **टीड वरक:**
  - यह सरकार के ढीतर वढलनन वढलगों और एजेंसलल को एक टीड के रूप ढें कारय करने की आवशुकतल पर बल देतल है ।
  - यह लुगों की आवशुकतलओं का प्रभावी सढलधलन करने के लयल वढलनन सरकारी संसथलओं के ढीच सहयोग और सढनवय को बढवल देतल है ।
- **पारदरशतल:**
  - यह 5T पहल का एक प्रढुख ततुत्व है । यह सरकारी प्रकरयलओं और नरलणयों को जनतल के प्रतलअधकी पारदरशी एवं जवलबदेह बनलने पर केंदुरतल है ।
  - इसढें सूचनाओं तक सुगढ पहुँच प्रदलन करना, नौकरशलही-लललफीतलशलही को कढ करना और सरकार के ढीतर नैतकी तथल जवलबदेह आचरण को बढवल देनल शलढलल है ।
- **प्ररदयोगकी:**
  - यह सरकारी करयों को सुवयवसथतल करने, सेवा वतलरण को बढलने और प्रकरयलओं को अधकी कुशल बनलने के लयलआधुनकी प्ररदयोगकी तथल डजलटल सलधनों के उलयुग को प्रुतुसलहतल करतल है ।
- **समय-सीडल:**
  - समय-सीडल का पहलू समय पर सेवाएँ प्रदलन करने के ढहतुत्व को रेखांकतल करतल है । 5T ढडल का उदुदेश्य सेवा वतलरण ढें हुने वलले वललंब को कढ करना और नलगरकल को सरकारी सेवाएँ समयबदुध तरलके से वतलरतल कयल जलनल सुनशलुतल करतल है ।
- **परवलरतन:**
  - अंततः 5T पहल का उदुदेश्य सरकारी एजेंसलल और वढलगों के कलढकलज ढें बदललव ललनल है । इसका उदुदेश्य सरकार को अधकी उतुतरदलदी, नलगरकल-केंदुरतल तथल परणलढुनढुख बनलनल है ।

## 5T पहल की उलयलधयलल:

- मार्च 2023 तक 5T पहल के तहत 6,872 हाई स्कूलों में वभिन्न बदलाव किये गए।
- वर्ष 2019-20 में नजी स्कूलों में छात्रों की संख्या 16,05,000 थी, कति वर्ष 2021-22 में छात्रों की संख्या घटकर 14,62,000 हो गई है। यानी सरकारी स्कूलों में नामांकन कराने व पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है।

## मो सरकार पहल:

- यह एक शासन व्यवस्था संबंधी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को वितरित करने के तरीके में बदलाव लाना और सार्वजनिक कार्यालयों की जवाबदेही तथा पारदर्शिता में सुधार करना है।
  - स्थानीय भाषा में "मो सरकार" का अर्थ है "मेरी सरकार"।
- रयिलटाइम फीडबैक तंत्र "मो सरकार" पहल की उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक है।
  - यहाँ तक कि मुख्यमंत्री सहित शीर्ष अधिकारियों के पास सरकारी संस्थानों से जुड़े नागरिकों के फोन नंबर उपलब्ध होते हैं।
- यह फीडबैक तंत्र नागरिकों के मुद्दों की पहचान करने, सरकारी अधिकारियों के प्रदर्शन का आकलन करने और आवश्यकता पड़ने पर उपचारात्मक कार्रवाई करने में मदद करता है।
- "मो सरकार" पहल को नौकरशाहों के बजाय जनता को शक्ति प्रदान करते हुए शासन व्यवस्था को अधिक साक्ष्य-आधारित, कुशल तथा न्यायसंगत बनाने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है।

## राज्यों में नीतिआयोग जैसी संस्था के कार्यान्वयन का प्रमुख कारण:

**नीति (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) आयोग** वर्ष 2017 तक एक वकिसति राष्ट्र बनने के दृष्टिकोण के साथ-साथ तेज़ और समावेशी आर्थिक विकास के लिये राज्यों को उनके योजना बोर्डों के स्थान पर अपने समान निकाय स्थापित करने में सहायता करेगा।

- प्रारंभ में इसका लक्ष्य मार्च 2023 तक सभी राज्यों में समान निकाय स्थापित करने से पूर्व 8 से 10 राज्यों में ऐसे निकाय स्थापित करना है।
  - चार राज्यों यानी कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और असम ने इस संबंध में पहले ही कार्य शुरू कर दिया है।
  - महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और गुजरात में जल्द ही कार्य शुरू होने की संभावना है।
- नीतिआयोग की भूमिका:
  - यह राज्य योजना बोर्डों की मौजूदा संरचना की जाँच करने हेतु एक टीम के गठन में मदद करेगा।
  - आगामी 4-6 महीनों में स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन (SIT) की संकल्पना तैयार करेगा।
    - उच्च गुणवत्ता वाले विश्लेषणात्मक कार्य और नीति सिफारिशें करने के लिये SIT में पेशेवरों के पार्श्व प्रवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- राज्य योजना बोर्डों को SIT के रूप में पुनर्गठित करने के अतिरिक्त नमिनलखित पर एक रूपरेखा तैयार की जाएगी:
  - नीति निर्माण में राज्यों का मार्गदर्शन करने हेतु।
  - सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों की नगिरानी एवं मूल्यांकन हेतु।
  - योजनागत लाभों के वितरण के लिये बेहतर तकनीक अथवा मॉडल का सुझाव देने हेतु।

## राज्यों में नीतिआयोग जैसी संस्थाएँ स्थापित करने की आवश्यकता:

- राज्य भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास चालक होते हैं। रक्षा क्षेत्र, रेलमार्ग और राजमार्ग जैसे उद्योगों को छोड़कर राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद की कुल वृद्धि दर राष्ट्रीय जीडीपी वृद्धि कहलाती है।
  - स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास मुख्यतः राज्य सूची के विषय हैं।
- व्यापार करने में सरलता, भूमि सुधार, बुनियादी ढाँचे के विकास, ऋण प्रवाह और शहरीकरण में सुधार में राज्य सरकारों की भूमिका अहम होती है, ये सभी निरंतर आर्थिक विकास के लिये महत्वपूर्ण हैं।
- अधिकांश राज्यों ने अपने योजना बोर्डों या विभागों को नवीनीकृत करने के लिये कोई प्रयास नहीं किया है, जो पहले योजना आयोग के साथ मलिकर कार्य करते थे तथा केंद्र के साथ समवर्ती राज्य पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में योगदान देते थे।
  - बड़ी संख्या में कार्यबल के साथ अधिकांश राज्यों के योजना विभाग लगभग नषिक्रयि हैं और उनके पास कार्यों को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है।

## अन्य राज्यों में भी समान पहलें:

- केरल राज्य योजना बोर्ड:
  - इस बोर्ड की प्राथमिक भूमिका के अंतर्गत वार्षिक आर्थिक समीक्षा तैयार करने के साथ-साथ पंचवर्षीय और वार्षिक दोनों योजनाएँ तैयार करना शामिल है।
  - यह इन योजनाओं के कार्यान्वयन की नगिरानी करता है, योजनाओं से संबंधित वभिन्न विभागों के साथ मलिकर सहयोग करता है और वकिंद्रीकरण इकाई के संचालन की देख-रेख करता है।
  - यह बोर्ड आयोग पर शोध भी करता है, केंद्रीय और बाह्य रूप से वतितपोषित कार्यक्रमों के लिये व्यावहारिक विश्लेषण तथा सिफारिशें प्रदान करता है व अध्यक्ष के लिये नीति विवरण तैयार करता है।
- सकला मशिन:
  - कर्नाटक राज्य सरकार ने कर्नाटक राज्य में नागरिकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर सेवाओं के वितरण की गारंटी प्रदान

- करने और उससे जुड़े तथा प्रासंगिक मामलों के लिये सकला मशिन शुरू कयि।  
◦ इस अधनियिम को कर्नाटक नागरकों को सेवाओं की गारंटी अधनियिम, 2011 कहा जाता है।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. अटल इनोवेशन मशिन की स्थापना कसिके अंतर्गत की गई है? (2019)

- (a) वजिज्ञान और प्रौद्योगिकी वभिग
- (b) श्रम और रोजगार मंत्रालय
- (c) नीति आयोग
- (d) कौशल विकास और उद्यमता मंत्रालय

उत्तर: (c)

??????:

प्रश्न. “वभिन्न स्तरों पर सरकारी तंत्र की प्रभावता तथा शासकीय तंत्र में जन-सहभागता अन्योन्याशरति होती है।” भारत के संदर्भ में इनके बीच संबंध पर चर्चा कीजिये। (2016)

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/the-5t-initiative-of-odisha>

